जागरण

22 March 2023

भारत में शहरी जल प्रबंधन के लिए उठाने होंगे उचित कदम

असित के बिस्वास
विजिटिंग प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी आफ ग्लासगो, यूके

सेसिलिया टोरटाजादा
प्रोफेसर, स्कूल आफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज, यूनिवर्सिटी आफ ग्लासगो, यूके

भारत में शहरी जल आपूर्ति एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन अव्यवस्थित है। आजादी के बाद 1980 तक सुधारों की गति बहुत धीमी रही थी। इसके बाद इसमें कुछ सुधार हुआ। 2015 से इसमें उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं, लेकिन अभी भी यह पर्याप्त नहीं है।

भारत में पर्याप्त पानी है, निवेश है, प्रबंधन एवं इंजीनियरिंग की विशेषज्ञता है और टेक्नोलाजी भी है। शहरी आबादी तक स्वच्छ जल की पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पाने के पीछे कोई तकनीकी या आर्थिक कमी वाला पक्ष नहीं है। ऐसा नहीं हो पाया है, क्योंकि इसके लिए केंद्र एवं राज्यों के स्तर पर पर्याप्त राजनीतिक इच्छा नहीं रही है। भारतीय राजनीति में जल प्रबंधन कभी प्रमुख मुद्दा नहीं रहा है। नेता इसमें तभी दिलचस्पी दिखाते हैं, जब बाढ़ या सूखा की स्थिति होती है। संकट खत्म होते ही चिंता खत्म हो जाती है।

इस दिशा में राजनीतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। सिंगापुर के उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। 1965 में सिंगापुर जब आजाद हुआ था, तब उसकी जल आपूर्ति एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन की व्यवस्था दिल्ली से खराब थी। तब वहां प्रधानमंत्री ली क्वान यू ने कमान संभाली थी। उन्होंने इस बात को समझा कि सिंगापुर को संभलना और आगे बढ़ना है, तो जल सुरक्षा महत्वपूर्ण है। उनके कार्यालय में तीन लोग यही देखते थे कि विभिन्न सरकारी नीतियों से जल प्रबंधन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ली का मानना था कि सभी राष्ट्रीय नीतियों को जल से जुड़ना चाहिए। इन प्रयासों का परिणाम सबके सामने है। 1985 आते-आते सिंगापुर वैश्विक स्तर पर शहरी जल प्रबंधन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बनकर सामने आ गया।

भारत में 'हर घर-नल से जल' कार्यक्रम, शौचालय निर्माण एवं खुले में शौच से मुक्ति जैसे कदमों ने अच्छे परिणाम दिखाए हैं। हालांकि अभी और भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। एक आधारभूत प्रश्न है कि भारत में एक व्यक्ति को स्वस्थ एवं बेहतर जीवन जीने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है। आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय का कहना है कि प्रत्येक शहरी नागरिक को प्रतिदिन 135 लीटर स्वच्छ जल मिलना चाहिए। यह 135 लीटर का आंकड़ा कहां से आया। इसे बस यूं ही कहीं से ले लिया गया। सिंगापुर में 1960-70 में हुए अध्ययन में पाया गया था कि घर में पानी का प्रयोग बढ़ने से स्वास्थ्य में सुधार होता है। इसमें यह भी पाया गया कि 75 लीटर प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति से ज्यादा पानी खर्च करने से स्वास्थ्य पर कोई अतिरिक्त सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। इसका अर्थ है कि 75 लीटर पानी प्रतिदिन लोगों के स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त है, 135 लीटर नहीं। अगर शहरों में पानी के प्रयोग को 75 लीटर प्रतिदिन पर लाया जा सके, जो इससे कई लाभ होंगे। इन्फ्रास्ट्रक्चर से लेकर सभी प्रकार के खर्च कम होंगे। खपत कम होगी, तो अपशिष्ट जल कम होगा, जिससे ट्रीटमेंट प्लांट पर दबाव कम होगा और पर्यावरण को भी लाभ होगा।

एक बात और, शौचालय आवश्यक हैं, लेकिन उनका निर्माण कर देना ही पर्याप्त नहीं है। हाल के वर्षों में लाखों नए शौचालय बने हैं, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं सोचा गया कि सेप्टिक टैंक में जो अपशिष्ट जमा हो रहा है, उसका प्रबंधन कैसे होगा। कनाडा और अमेरिका जैसे कम आबादी वाले देशों में भी सेप्टिक टैंक का प्रबंधन बड़ी चुनौती है, जबकि वहां सेप्टिक टैंक आदि के निर्माण को लेकर सख्त नियमन हैं। भारत में यदि इस दिशा में प्रयास नहीं हुए तो अगले एक दशक में 10 बड़े शहर स्वच्छ पेयजल की बाधित आपूर्ति एवं प्रदूषित जल के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के शिकार होंगे। बेहतर प्रबंधन से संकट को टाला जा सकता है। भारत भी प्रयास करे तो अगले 20 साल में सिंगापुर जैसा शहरी जल प्रबंधन कर सकता है।

इस समय जल आपूर्ति की व्यवस्था के तहत जो पानी मिलता है, उसे लेकर लोगों को यह विश्वास नहीं है कि वह पीने के लायक है। इसलिए वे अपने घरों में आरओ व अन्य लोकल ट्रीटमेंट सिस्टम लगा रहे हैं। बोतलबंद पानी का प्रयोग बढ़ा है। इस समय देश में सालाना करीब 60 लाख लीटर बोतलबंद पानी का प्रयोग हो रहा है, जिसकी लागत करीब 4.5 अरब डालर है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि भारत में लोग जो बोतलबंद पानी खरीद रहे हैं, वह भी बहुत सुरक्षित नहीं है। इनमें 40 प्रतिशत सैंपल प्रदूषित पाए गए हैं।